यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/36/2018 **दिनांक :** 14.04.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

एआईबीईए की माँग – आईसीआईसीआई बैंक तथा एक्सिस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाये

उपरोक्त विषय में एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् द्वारा 13.04.2018 को एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई है। हम इसका अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर कर है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

भारत रत्न डा० भीमराव अम्बेडकर के 127वें जन्मदिवस की सभी सदस्यों को हार्दिक बधाईयाँ

सी.एच. वेंकटचलम्, महामंत्री, एआईबीईए द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति **13.04.2018**

- **हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की माँगों का विरोध करते हैं**
- **हम आईसीआईसीआई बैंक तथा एक्सिस बैंक के राष्ट्रीयकरण की माँग करते हैं**

जब से पंजाब नैशनल बैंक–नीरव मोदी धोखाधड़ी का मामला सामने आया, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के निजीकरण की माँग करने वाली विभिन्न कोनों से आवाजें बुलन्द हुईं। यह एसोचैम से मांग को करने के साथ शुरू हुआ, इसके बाद फिक्की, अरविन्द सुब्रमण्यम, अरविंद पनगारिया, नंदन नीलकेणी, विनोद राय इत्यादि। वे एक परिपूर्ण वाद्यमंडली के तौर पर प्रस्तुति दे रहे थे। उनका एकमात्र तर्क था कि पीएनबी धोखाधड़ी बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्र स्वामित्व की अक्षमता के कारण हुई है।

वे आसानी से इस तथ्य को भूल गए हैं कि 1947 (स्वतंत्रता) तथा 1969 (बैंकों का राष्ट्रीयकरण) के बीच, **736 निजी बैंक** इन बैंकों के निजी मालिकों द्वारा कुप्रबंधन के कारण ढह गए और बन्द हो गए।

1969 के बाद भी, **36 निजी बैंक** ढह गए/अस्तित्व से बाहर चले गए और अन्य बैंकों के साथ विलय हो गए।

1969	बैंक ऑफ बिहार
1970	नैशनल बैंक ऑफ लाहौर
1971	ईस्टर्न बैंक
1974	कृष्णराव बल्देव बैंक
1976	बेलगाम बैंक
1985	लक्ष्मी कॉमर्शियल बैंक

जारी पृष्ठ 2

1986	मिराज स्टेट बैंक
1986	हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक
1990	ट्रेडर्स बैंक लि0
1990	बैंक ऑफ तमिलनाड
1990	बैंक ऑफ थंजावुर
1991	परूर सेण्ट्रल बैंक
1991	पूर्वांचल बैंक
1993	बैंक ऑफ कराड लि0
1995	काशीनाथ सेठ बैंक
1997	पंजाब को–ऑपरेटिव बैंक लि0
1997	बरी दोआब बैंक लि0
1999	बरेली बैंक लि0
1999	20 सेंचुरी फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लि0
1999	ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट
1999	सिक्किम बैंक लिमिटेड
2000	टाईम्स बैंक लि0
2001	बैंक ऑफ मदुरा
2002	बनारस स्टेट बैंक लि0
2003	नेदुंगदी बैंक लि0
2004	साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक
2004	बैंक मस्कट एसएओजी
2004	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि0
2006	बैंक ऑफ पंजाब
2006	गणेश बैंक ऑफ कुरूंडवाड
2006	यूएफजे बैंक लि0
2007	यूनाईटेड वेस्टर्न बैंक
2007	लॉर्ड कृष्णा बैंक
2007	संगली बैंक
2007	भारत ओवरसीज बैंक
2008	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब

फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की माँग करने का प्रचार ये निहित स्वार्थ, कॉर्पोरेट घराने और उनके मुखपत्र समय–समय पर करते रहे हैं।

यदि निजी बैंक वास्तव में कुशल हैं, तो ये बैंक क्यों बंद हो गए और अन्य के साथ विलय कर दिये गए। इनमें से ज्यादातर बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ विलय कर दिए गए। कई निजी बैंकों की विफलता के जहर को निगलने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नीलकंठ महादेव बन गए और यह हास्यास्पद है कि एसोचैम अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए कह रहा है। हम उनके लालच को समझते हैं लेकिन वे यह दावा नहीं कर सकते कि निजी बैंक अधिक कुशल हैं।

दूसरे, बैंकों में चिन्ताजनक रूप से बढ़ते हुए खराब ऋणों को लें। अपराधी कौन हैं और चूककर्ता कौन हैं ? क्या वे सभी निजी कंपनियां, उद्योगपति और कॉर्पोरेट घराने नहीं हैं ? एनपीए के 12 मामलों को दिवालियापन और दिवालियापन की कार्यवाही के लिए एनसीएलटी को भेजा गया है जिसमें रू0 253,000 करोड़ शामिल हैं। वे कौन हैं ? क्या वे सभी शीर्ष निजी कॉर्पोरेट उधारकर्ता नहीं हैं। उन्होंने ऋणों को क्यों नहीं चुकाया ? क्या यही उनकी दक्षता है ? क्या बैंकों का निजीकरण होना चाहिए और इन लोगों को सौंप दिये जाने चाहिए ?

जारी पृष्ठ 3

जानबूझकर चूककर्ता – सभी निजी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं

बैंक	जानबूझकर चूककर्ता – निजी कंपनियां	
	जानबूझकर चूककर्ताओं की संख्या	चूक की राशि
इलाहाबाद बैंक	164	3,590
आन्ध्रा बैंक	401	3,979
बैंक ऑफ बड़ौदा	255	5,600
बैंक ऑफ इण्डिया	403	5,418
बैंक ऑफ महाराष्ट्रा	137	985
केनरा बैंक	490	4,590
सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	772	6,146
कॉर्पोरेशन बैंक	122	2,182
देना बैंक	227	1,861
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	85	3,937
इण्डियन बैंक	64	1,063
इण्डियन ओवरसीज बैंक	527	4,485
ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	429	4,236
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	27	283
पंजाब नैशनल बैंक	1,084	14,588
सिण्डिकेट बैंक	204	1,163
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	1,664	28,257
यूको बैंक	651	5,654
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	832	5,376
यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया	388	1,739
विजया बैंक	137	4,917
कुल	**9,063**	**1,10,050**

क्या वे कह सकते हैं कि ये 9063 कंपनियां निजी स्वामित्व वाली नहीं हैं। उनकी दक्षता को क्या हुआ। उन्होंने दिसम्बर 2017 तक रू0 110,050 करोड़ तक के बैंक ऋणों की जानबूझकर चूक क्यों की ? क्या यह सार्वजनिक बचतों की खुली लूट नहीं है ? फिर भी वे निजी क्षेत्र की दक्षता की बात करते हैं !

निजी बैंकों में खराब ऋण – उनकी दक्षता का एक और सूची

बैंक – दिसम्बर 2017 को	सकल एनपीए/ करोड़
आईसीआईसीआई बैंक लि0	**45051**
एक्सिस बैंक लि0	**22662**
एचडीएफसी बैंक लि0	8176
जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि0	6232
कोटक महिन्द्रा बैंक लि0	3715
यस बैंक लि0	2974
आईडीएफसी बैंक लि0	2777

जारी पृष्ठ 4

करूर वैश्य बैंक लि0	2663
फैडरल बैंक लि0	2161
कर्नाटका बैंक लि0	1784
साउथ इण्डियन बैंक लि0	1775
इंडसइंड बैंक लि0	1499
लक्ष्मी विलास बैंक लि0	1427
तमिलनाड मर्केन्टाईल बैंक लि0	1355
सिटी यूनियन बैंक लि0	860
कैथोलिक सीरियन बैंक लि0	746
रत्नाकर बैंक लि0	580
धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	446
बन्धन बैंक लि0	386
डीसीबी बैंक लि0	354
नैनीताल बैंक लि0	172
निजी बैंकों में कुल खराब त्रण/एनपीए – दिस. 2017	**107795 करोड़**

केवल 5 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (एसबीआई, बैंक ऑफ इण्डिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक) के एनपीए आईसीआईसीआई बैंक के एनपीए से अधिक है। 16 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, एनपीए आईसीआईसीआई बैंक के एनपीए से कम हैं। फिर भी वे दक्षता की बात करते हैं !

हम माँग करते हैं – आईसीआईसीआई बैंक तथा एक्सिस बैंक का राष्ट्रीयकरण करें :

हर कोई अब जानता है कि आईसीआईसीआई बैंक तथा एक्सिस बैंक में निजी क्षेत्र दक्षता के तथाकथित चैंपियनों के बारे में क्या वास्तविकता है। इन दोनों बैंकों में कुल मिलाकर रू0 9 लाख करोड़ तक लोगों की जमाराशियां हैं। हमें इस सार्वजनिक धन की रक्षा करने की आवश्यकता है। वे निजी बैंकों में बेहतर प्रबंधन की बात करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक को एक आदर्श के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। उसको अब क्या हुआ। ऋणों की मंजूरी में भ्रष्टाचार और भाई–भतीजावाद के गंभीर आरोप हैं। कम प्रावधानों और खराब ऋणों को बार–बार ढकने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये सभी अनैतिक चीजें लम्बे समय से चल रही हैं। केवल शीर्ष अधिकारियों को बदलना पर्याप्त नहीं होगा। यह सही समय है कि सरकार को आईसीआईसीआई बैंक तथा एक्सिस बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के लिए आगे आना चाहिए।

ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री